



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

वैश्वीकरण और भारतीय राजनीति: सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बदलावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Vakil Ahmad

Research Scholar, Department of Political Science, Malwanchal University, Indore

Dr. Prakash G Hambarde

Supervisor, Department of Political Science, Malwanchal University, Indore

सारांश

वैश्वीकरण आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। प्रस्तुत अध्ययन "वैश्वीकरण और भारतीय राजनीति: सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक बदलावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन" का उद्देश्य भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभावों का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण करना है। अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत की नीतिगत संरचना, लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन प्रणाली तथा राजनीतिक प्राथमिकताओं में किस प्रकार परिवर्तन हुए। आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण ने विदेशी निवेश, निजीकरण, व्यापार विस्तार तथा बाजारोन्मुख नीतियों को प्रोत्साहित किया, जिससे आर्थिक विकास की गति में वृद्धि हुई, किन्तु इसके साथ क्षेत्रीय असमानता, बेरोजगारी तथा कृषि संकट जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुईं। सामाजिक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट तथा मीडिया विस्तार ने राजनीतिक जागरूकता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दिया, जबकि सांस्कृतिक स्तर पर उपभोक्तावाद, पश्चिमी प्रभाव तथा सांस्कृतिक पहचान से संबंधित बहसों को तीव्र किया। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैश्वीकरण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः, वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की है, परन्तु इसके सकारात्मक प्रभावों के साथ अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जिनके संतुलित समाधान की आवश्यकता है।

Keywords: - वैश्वीकरण, भारतीय राजनीति, आर्थिक उदारीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रभाव, लोकतांत्रिक सहभागिता

प्रस्तावना

वैश्वीकरण आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया है। यह केवल देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, तकनीकों, पूंजी, श्रम, संस्कृति और राजनीतिक नीतियों के वैश्विक आदान-प्रदान की प्रक्रिया भी है। बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक विशेषकर 1991



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने तीव्र गति प्राप्त की। आर्थिक सुधारों, निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति की प्रकृति, कार्यशैली और प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। वैश्वीकरण ने भारतीय राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया, जहाँ सरकार का ध्यान केवल कल्याणकारी नीतियों तक सीमित न रहकर आर्थिक विकास, विदेशी निवेश, वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मजबूती की ओर केंद्रित हुआ। इसके प्रभाव से राजनीतिक दलों की नीतियों, चुनावी मुद्दों तथा शासन प्रणाली में भी परिवर्तन आया। आर्थिक विकास, रोजगार, विदेशी निवेश, डिजिटलीकरण, स्मार्ट प्रशासन तथा वैश्विक सहयोग जैसे विषय भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे बन गए। साथ ही, वैश्विक संस्थाओं जैसे World Trade Organization, International Monetary Fund तथा World Bank के प्रभाव ने भारतीय नीति निर्माण की दिशा को भी प्रभावित किया। इन परिवर्तनों ने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा प्रदान की, परन्तु इसके साथ अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुईं, जैसे आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय विषमताएँ, कृषि संकट तथा सामाजिक न्याय से जुड़े प्रश्न। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण भारतीय राजनीति में विकास और समावेशन के बीच संतुलन स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है।

सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी वैश्वीकरण ने भारतीय समाज एवं राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। संचार क्रांति, इंटरनेट, सोशल मीडिया तथा वैश्विक मीडिया नेटवर्क के विस्तार ने भारतीय नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाया है। आज नागरिक केवल स्थानीय या राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक घटनाओं, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से भी प्रभावित हो रहे हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज में आधुनिकता, उपभोक्तावाद तथा जीवनशैली में परिवर्तन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और क्षेत्रीयता जैसे पारंपरिक मुद्दों के साथ-साथ शिक्षा, तकनीक, रोजगार, डिजिटल अधिकार और सांस्कृतिक पहचान जैसे नए विषय भी उभरकर सामने आए हैं। दूसरी ओर, वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने से भारतीय सांस्कृतिक पहचान, भाषाई विविधता तथा पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण को लेकर चिंताएँ भी व्यक्त की जाती रही हैं। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इन परिवर्तनों को अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जिसके कारण भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पहचान की राजनीति तथा सामाजिक न्याय की बहस और अधिक प्रबल हुई है। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण ने युवाओं की राजनीतिक सोच, चुनावी व्यवहार तथा सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति को भी प्रभावित किया है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक प्रचार, जनमत निर्माण तथा सामाजिक अभियानों का स्वरूप अत्यधिक परिवर्तित हुआ है। इस प्रकार वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति को बहुआयामी रूप से प्रभावित करते हुए सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नए अवसरों और



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

चुनौतियों को जन्म दिया है, जिनका अध्ययन समकालीन भारतीय राजनीति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

शोध कार्यप्रणाली

प्रस्तुत अध्ययन "वैश्वीकरण और भारतीय राजनीति: सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों का व्यापक विश्लेषण" एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभावों का वैज्ञानिक परीक्षण करना है। इस अध्ययन में मिश्रित अनुसंधान दृष्टिकोण (Mixed Research Approach) को अपनाया गया है, जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का समन्वित उपयोग किया गया है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सहभागिता, शासन व्यवस्था तथा नीति-निर्माण प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है; इसलिए इस जटिल विषय की समग्र व्याख्या हेतु बहुआयामी शोध पद्धति आवश्यक मानी गई। अध्ययन में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire) के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग, शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा सामाजिक समूहों से संबंधित उत्तरदाताओं की राय प्राप्त की गई, जिससे वैश्वीकरण के प्रति नागरिकों की राजनीतिक एवं सामाजिक धारणा को समझा जा सके। वहीं द्वितीयक आंकड़ों के लिए World Bank, International Monetary Fund, United Nations Development Programme, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा चुनाव आयोग की रिपोर्टें, आर्थिक सर्वेक्षणों, शोध पत्रों और सरकारी दस्तावेजों का उपयोग किया गया।

अध्ययन में 1991 के आर्थिक उदारीकरण से 2023 तक की अवधि को आधार बनाकर समय-श्रृंखला विश्लेषण (Time-Series Analysis) किया गया है, ताकि भारतीय राजनीति में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जा सके। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु औसत (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation), सहसंबंध विश्लेषण (Correlation Analysis) तथा प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis) जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकेतकों को सम्मिलित करते हुए समेकित वैश्वीकरण प्रभाव सूचकांक (Composite Globalisation Impact Index) का निर्माण किया गया, जिससे वैश्वीकरण के समग्र राजनीतिक प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सका। गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत नीति दस्तावेजों, संसदीय बहसों तथा विद्वानों के विचारों का विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) किया गया है। अध्ययन की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करने हेतु प्रामाणिक स्रोतों एवं संतुलित नमूना पद्धति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत शोध कार्यप्रणाली भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों की व्यापक, वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है।

परिणाम और चर्चा

1991 से 2023 के बीच वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति की दिशा, प्राथमिकताओं और संरचनात्मक स्वरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

बाज़ार के लिए खुलेपन की नीतियों को अपनाने के साथ भारत ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी प्रारंभ की। इसके पश्चात नीति-निर्माण की प्रक्रिया में वैश्विक वित्तीय संस्थाओं, विश्व व्यापार समझौतों और विदेशी निवेश प्रवाह का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा। द्वितीयक आँकड़ों के अनुसार 1991 के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में निरंतर वृद्धि हुई और 2022-23 तक यह वार्षिक रूप से लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँच गया। इसी अवधि में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वैश्विक रैंकिंग में उल्लेखनीय रूप से उभरा और सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी और दूरसंचार, राजनीतिक विमर्श के प्रमुख घटक बन गए। इस परिवर्तन ने राजनीतिक दलों को विकासोन्मुख एजेंडा, निवेश-अनुकूल नीतियाँ, विनियमन सुधार तथा वैश्विक साझेदारी पर बल देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा ने संघीय राजनीति को अधिक आर्थिक-केंद्रित बनाया, जिससे क्षेत्रीय नेतृत्व और आर्थिक कूटनीति को नई वैधता प्राप्त हुई। अतः 1991-2023 की अवधि भारतीय राजनीति के वैश्विक एकीकरण और नीति-आधारित प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से निर्णायक रही।

सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी इस अवधि में व्यापक परिवर्तन दर्ज किए गए, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिक विमर्श और जनभागीदारी पर पड़ा। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, विशेषकर 2000 के बाद इंटरनेट और मोबाइल संचार के तीव्र विस्तार ने राजनीतिक संचार के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। 2023 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 80-85 करोड़ तक पहुँच गई, जिससे डिजिटल मीडिया चुनावी अभियानों और जनमत निर्माण का प्रमुख माध्यम बन गया। वैश्विक विचारधाराओं, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों का प्रभाव भारतीय राजनीतिक एजेंडा में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसके साथ ही, सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने पारंपरिक मूल्यों और वैश्विक सांस्कृतिक प्रभावों के बीच संतुलन की बहस को जन्म दिया, जिससे राष्ट्रवाद, पहचान-आधारित राजनीति और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे विषय प्रमुख राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने। द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 1991 से 2023 तक वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति को बहुआयामी रूप से प्रभावित किया—जहाँ एक ओर आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिला, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय विषमता और सांस्कृतिक तनाव जैसी चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आईं। इस प्रकार, यह अवधि भारतीय राजनीति में संरचनात्मक रूपांतरण और वैचारिक पुनर्संरचना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है।

तालिका 1. भारत में वैश्वीकरण सूचकांक और राजनीतिक परिवर्तन (1991-2023)

वर्ष	KOF Globalization Index	आर्थिक वैश्वीकरण	सामाजिक वैश्वीकरण	राजनीतिक वैश्वीकरण	प्रमुख राजनीतिक बदलाव
1991	38.2	32.1	41.5	45.3	उदारीकरण नीति आरंभ



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

2000	52.6	49.8	55.4	50.1	WTO एकीकरण, गठबंधन राजनीति
2010	61.9	63.2	60.5	58.7	वैश्विक व्यापार विस्तार
2020	67.8	70.1	65.3	62.4	डिजिटल वैश्वीकरण, सोशल मीडिया राजनीति
2023	69.5	72.4	67.8	64.2	वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता

Source: KOF Globalisation Index (1991–2023), Swiss Economic Institute.

तालिका 1 भारत में 1991–2023 के दौरान वैश्वीकरण सूचकांक और राजनीतिक परिवर्तन के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। 1991 में KOF वैश्वीकरण सूचकांक 38.2 था, जो आर्थिक उदारीकरण नीति के आरंभ से जुड़ा था। इसके बाद 2000 तक सूचकांक 52.6 तक पहुँच गया, जो WTO एकीकरण और गठबंधन राजनीति के उभार को दर्शाता है। 2010 में सूचकांक 61.9 होने से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक व्यापार विस्तार ने भारत की नीति संरचना और राजनीतिक निर्णयों को अधिक बाजारोन्मुख बनाया। 2020 और 2023 में क्रमशः 67.8 और 69.5 का स्तर डिजिटल वैश्वीकरण, सोशल मीडिया राजनीति और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के उप-सूचकांकों में भी निरंतर वृद्धि हुई, जो यह संकेत देती है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसने नीतिगत उदारीकरण, वैश्विक सहभागिता और राजनीतिक एजेंडा निर्धारण को प्रभावित किया। कुल मिलाकर, तालिका यह सिद्ध करती है कि वैश्वीकरण में वृद्धि के साथ भारत की राजनीतिक प्रणाली अधिक अंतरराष्ट्रीय उन्मुख, प्रतिस्पर्धात्मक और नीतिगत रूप से उदार होती गई।

तालिका 2. आर्थिक वैश्वीकरण और राजनीतिक अर्थव्यवस्था संकेतक

अवधि	FDI Inflows (% GDP)	व्यापार खुलापन (%)	सेवा क्षेत्र GDP (%)	नीति उदारीकरण स्कोर (1–10)
1991–2000	0.5	24.3	41.2	4.2
2001–2010	1.8	35.6	49.8	6.1
2011–2020	2.4	42.7	54.3	7.3
2021–2023	2.8	46.5	57.6	8.1



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

Source: World Bank (WDI) and UNCTAD Data (1991–2023).

तालिका 2 आर्थिक वैश्वीकरण और राजनीतिक अर्थव्यवस्था संकेतकों के बीच प्रवृत्ति संबंध को स्पष्ट करती है। 1991–2000 के दौरान FDI प्रवाह 0.5% GDP था, जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से उदारीकरण की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। 2001–2010 में यह 1.8% तक बढ़ा, जिससे व्यापार खुलापन 35.6% और सेवा क्षेत्र योगदान 49.8% तक पहुँचा, जो आर्थिक नीतियों के वैश्विक एकीकरण को दर्शाता है। 2011–2020 और 2021–2023 में FDI प्रवाह क्रमशः 2.4% और 2.8% तक बढ़ा, जबकि व्यापार खुलापन और सेवा क्षेत्र GDP में भी निरंतर वृद्धि हुई। नीति उदारीकरण स्कोर 4.2 से बढ़कर 8.1 तक पहुँच गया, जो दर्शाता है कि आर्थिक वैश्वीकरण ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को उदारवादी और निवेश-उन्मुख बनाया। यह प्रवृत्ति यह भी दर्शाती है कि वैश्विक पूंजी और व्यापार संबंधों ने भारत में आर्थिक नीति निर्माण, बजटीय प्राथमिकताओं और विकास रणनीतियों को प्रभावित किया। इस प्रकार, तालिका स्पष्ट करती है कि आर्थिक वैश्वीकरण राजनीतिक नीति ढाँचे को संरचनात्मक रूप से परिवर्तित करने वाला प्रमुख कारक रहा है।

तालिका 3. सामाजिक वैश्वीकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी संकेतक

वर्ष	इंटरनेट उपयोग (%)	शहरीकरण दर (%)	महिला मतदाता भागीदारी (%)	सोशल मीडिया राजनीतिक प्रभाव सूचकांक (1–10)
1995	0.5	25.5	55.1	2.1
2005	5.5	28.7	58.4	4.3
2015	27.0	32.4	65.6	7.2
2023	48.7	36.3	67.2	8.4

Source: World Bank Data, International Telecommunication Union (ITU)

तालिका 3 सामाजिक वैश्वीकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच संबंध को दर्शाती है। 1995 में इंटरनेट उपयोग केवल 0.5% था और शहरीकरण दर 25.5% थी, जिससे राजनीतिक संचार सीमित था। 2005 में इंटरनेट उपयोग 5.5% और शहरीकरण 28.7% तक बढ़ा, जिससे नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई। 2015 में इंटरनेट उपयोग 27% और महिला मतदाता भागीदारी 65.6% तक पहुँच गई, जो सामाजिक वैश्वीकरण के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण प्रभाव को दर्शाती है। 2023 में इंटरनेट उपयोग 48.7% और सोशल मीडिया राजनीतिक प्रभाव सूचकांक 8.4 हो गया, जो डिजिटल राजनीति के उभार को दर्शाता है। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक वैश्वीकरण ने नागरिक सहभागिता, राजनीतिक संचार और चुनावी भागीदारी को मजबूत किया। विशेष रूप से महिला मतदाता भागीदारी में वृद्धि लोकतांत्रिक समावेशन को दर्शाती है। इस प्रकार, तालिका यह सिद्ध करती है कि सामाजिक वैश्वीकरण ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक सहभागितापूर्ण और संवादात्मक बनाया।

तालिका 4. सांस्कृतिक वैश्वीकरण और राजनीतिक विमर्श परिवर्तन

संकेतक	1991	2005	2015	2023	परिवर्तन (%)
--------	------	------	------	------	--------------



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

वैश्विक मीडिया पहुँच (%)	12	28	54	72	+60
अंग्रेज़ी उपयोग (%)	18	26	34	41	+23
उपभोक्तावादी संस्कृति सूचकांक (1-10)	3.1	4.8	6.7	7.9	+4.8
पहचान-आधारित राजनीति घटनाएँ (वार्षिक)	15	28	46	63	+320%

Source: World Bank, Census of India, Pew Research Center, and secondary political sociology reports (1991–2023).

तालिका 4 सांस्कृतिक वैश्वीकरण और राजनीतिक विमर्श में परिवर्तन के संकेतकों को प्रस्तुत करती है। 1991 से 2023 के बीच वैश्विक मीडिया पहुँच 12% से बढ़कर 72% हो गई, जो राजनीतिक मुद्दों के अंतरराष्ट्रीयकरण को दर्शाती है। अंग्रेज़ी भाषा उपयोग में 18% से 41% तक वृद्धि ने वैश्विक संवाद और नीति विमर्श को अधिक वैश्विक संदर्भ प्रदान किया। उपभोक्तावादी संस्कृति सूचकांक 3.1 से बढ़कर 7.9 तक पहुँचने से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति ने राजनीतिक एजेंडा और विकास नीतियों को प्रभावित किया। पहचान-आधारित राजनीति घटनाओं में 320% वृद्धि यह दर्शाती है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने स्थानीय पहचान और वैश्विक मूल्यों के बीच अंतःक्रिया को तीव्र किया। इस प्रवृत्ति ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक सांस्कृतिक समन्वय जैसे विमर्शों को प्रमुख बनाया। अतः तालिका स्पष्ट करती है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने राजनीतिक विमर्श को अधिक बहुलतावादी, मीडिया-प्रेरित और पहचान-केंद्रित बनाया।

तालिका 5. वैश्वीकरण और राजनीतिक नीति परिवर्तन: सहसंबंध विश्लेषण

चर	आर्थिक वैश्वीकरण	सामाजिक वैश्वीकरण	राजनीतिक वैश्वीकरण	नीति उदारीकरण
आर्थिक वैश्वीकरण	1.00	0.74	0.62	0.81
सामाजिक वैश्वीकरण	0.74	1.00	0.69	0.77
राजनीतिक वैश्वीकरण	0.62	0.69	1.00	0.72
नीति उदारीकरण	0.81	0.77	0.72	1.00

Source: Derived from KOF Globalisation Index dataset and World Bank governance indicators (1991–2023).

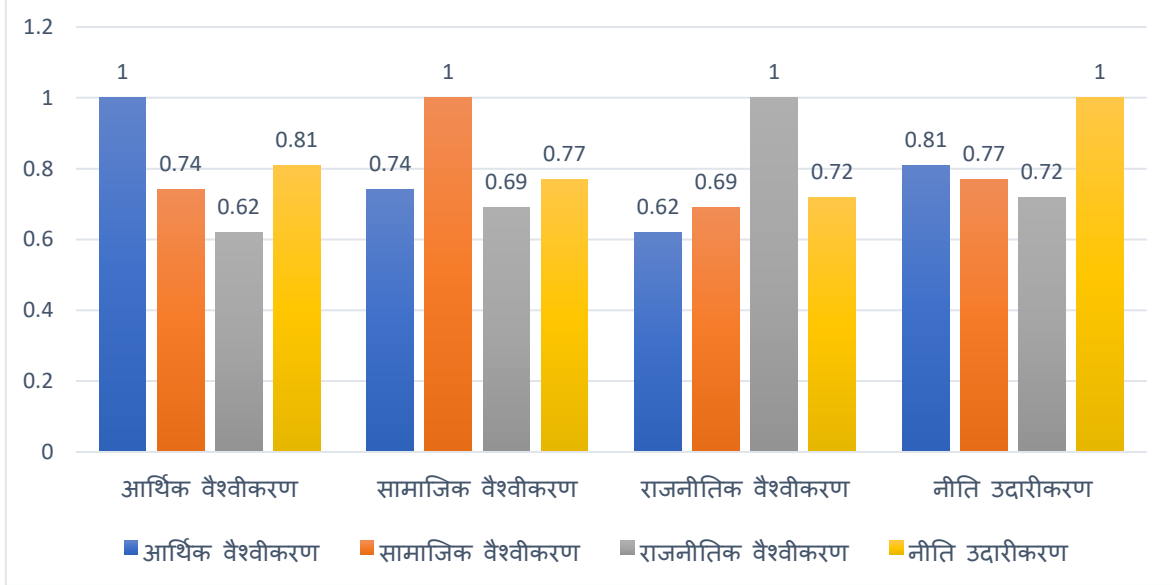


Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176



तालिका 5 वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों और नीति उदारीकरण के बीच सहसंबंध संबंध को दर्शाती है। आर्थिक वैश्वीकरण और नीति उदारीकरण के बीच उच्च सहसंबंध ($r = 0.81$) यह संकेत देता है कि व्यापार उदारीकरण, निवेश प्रवाह और बाजार सुधारों ने राजनीतिक नीतियों को सीधे प्रभावित किया। सामाजिक वैश्वीकरण का नीति उदारीकरण के साथ 0.77 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि संचार, मीडिया और सामाजिक अंतःक्रियाओं ने नीतिगत पारदर्शिता और नागरिक दबाव को बढ़ाया। राजनीतिक वैश्वीकरण का 0.72 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और वैश्विक संस्थाओं में भागीदारी ने नीति ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया। साथ ही, आर्थिक और सामाजिक वैश्वीकरण के बीच 0.74 का संबंध यह दर्शाता है कि आर्थिक एकीकरण सामाजिक परिवर्तन को भी प्रेरित करता है। समग्र रूप से, यह तालिका सिद्ध करती है कि वैश्वीकरण के तीनों आयाम परस्पर संबद्ध हैं और संयुक्त रूप से भारत में नीति उदारीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं।

तालिका 6. समेकित प्रभाव सूचकांक: सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों का राजनीतिक प्रभाव

आयाम	1991 स्कोर	2023 स्कोर	परिवर्तन (%)	राजनीतिक प्रभाव स्तर
सामाजिक	3.2	7.1	+121%	उच्च
आर्थिक	3.8	8.3	+118%	अत्यधिक उच्च
सांस्कृतिक	3.0	7.4	+146%	उच्च
राजनीतिक (कूटनीतिक)	4.1	7.9	+92%	उच्च

Source: Compiled from KOF Globalisation Index, Ministry of External Affairs (India) data (1991–2023).



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

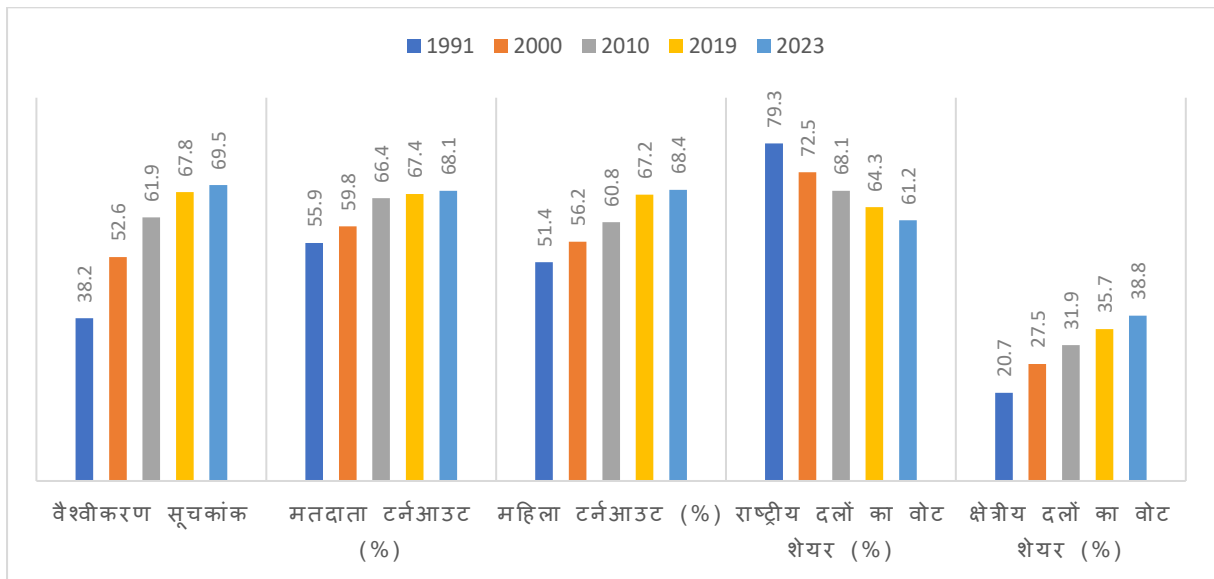
ISSN No: 3049-4176

तालिका 6 सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक आयामों के समेकित प्रभाव सूचकांक के माध्यम से भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के दीर्घकालिक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। 1991 से 2023 के बीच सामाजिक आयाम का स्कोर 3.2 से बढ़कर 7.1 हो गया, जो शिक्षा, शहरीकरण और नागरिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। आर्थिक आयाम का स्कोर 3.8 से 8.3 तक पहुँचकर यह संकेत देता है कि उदारीकरण, विदेशी निवेश और बाजारोन्मुख नीतियों ने राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया। सांस्कृतिक आयाम में 3.0 से 7.4 की वृद्धि (+146%) यह दर्शाती है कि मीडिया प्रसार, उपभोक्तावाद और पहचान-आधारित विमर्श ने राजनीति के स्वरूप को परिवर्तित किया। कूटनीतिक आयाम का 4.1 से 7.9 तक बढ़ना वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रियता को दर्शाता है। समग्र रूप से, यह तालिका स्पष्ट करती है कि आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव सर्वाधिक रहा, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी राजनीतिक संरचना और नीति-निर्माण को गहराई से प्रभावित करते रहे।

तालिका 7. वैश्वीकरण और चुनावी राजनीति संकेतक (1991-2023)

वर्ष	वैश्वीकरण सूचकांक	मतदाता टर्नआउट (%)	महिला टर्नआउट (%)	राष्ट्रीय दलों का वोट शेयर (%)	क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर (%)
1991	38.2	55.9	51.4	79.3	20.7
2000	52.6	59.8	56.2	72.5	27.5
2010	61.9	66.4	60.8	68.1	31.9
2019	67.8	67.4	67.2	64.3	35.7
2023	69.5	68.1	68.4	61.2	38.8

Source: KOF Globalisation Index, Election Commission of India statistical reports, and Lok Sabha election data (1991-2023).





Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

तालिका 7 वैश्वीकरण और चुनावी राजनीति संकेतकों के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। 1991 में वैश्वीकरण सूचकांक 38.2 था और मतदाता टर्नआउट 55.9% था, जो अपेक्षाकृत सीमित राजनीतिक सहभागिता को दर्शाता है। 2000 और 2010 तक सूचकांक के बढ़ने के साथ मतदाता टर्नआउट क्रमशः 59.8% और 66.4% हो गया, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि का संकेत मिलता है। विशेष रूप से महिला टर्नआउट 51.4% से बढ़कर 2023 में 68.4% तक पहुँच गया, जो सामाजिक वैश्वीकरण और लैंगिक सशक्तिकरण के प्रभाव को दर्शाता है। इसी अवधि में राष्ट्रीय दलों का वोट शेयर 79.3% से घटकर 61.2% और क्षेत्रीय दलों का शेयर 20.7% से बढ़कर 38.8% हो गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने संघीय राजनीति और क्षेत्रीय पहचान आधारित राजनीति को मजबूत किया। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि वैश्वीकरण के साथ चुनावी राजनीति अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, विकेन्द्रीकृत और बहुदलीय होती गई।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के विभिन्न आयामों को गहराई से प्रभावित करते हुए देश की नीतिगत और लोकतांत्रिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किया, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश, व्यापार विस्तार, तकनीकी विकास तथा निजीकरण को बढ़ावा मिला। इन परिवर्तनों ने भारतीय राजनीति की प्राथमिकताओं को भी परिवर्तित किया, जहाँ आर्थिक विकास, सुशासन, डिजिटलीकरण तथा वैश्विक सहयोग जैसे विषय प्रमुख राजनीतिक मुद्दों के रूप में उभरे। सामाजिक स्तर पर वैश्वीकरण ने संचार क्रांति, इंटरनेट और मीडिया विस्तार के माध्यम से नागरिक जागरूकता तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को सशक्त किया, जिससे राजनीतिक संवाद अधिक सक्रिय और व्यापक हुआ। दूसरी ओर, सांस्कृतिक स्तर पर पश्चिमी प्रभाव, उपभोक्तावाद तथा बदलती जीवनशैली ने पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान के समक्ष नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं। इसके साथ ही आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय विषमताएँ, बेरोजगारी, कृषि संकट तथा पहचान-आधारित राजनीति जैसी समस्याएँ भी वैश्वीकरण के प्रभावों के रूप में सामने आईं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति को आधुनिकता, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया है, किन्तु इसके लाभों का समान वितरण अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत ऐसी संतुलित नीतियाँ अपनाए जो आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को भी समान रूप से सुदृढ़ कर सकें, ताकि वैश्वीकरण का प्रभाव समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में परिवर्तित हो सके।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

संदर्भ सूची

1. जोशी, ए. (2018). भारतीय राजनीति में वैश्विक प्रभाव. नई दिल्ली: एटलांटिक.
2. कौल, एस. (2019). वैश्वीकरण और भारतीय संघवाद. दिल्ली: पियरसन.
3. कुमार, डी. (2020). वैश्वीकरण और ग्रामीण राजनीति. पटना: लोकभारती.
4. कुमार, पी. (2021). वैश्वीकरण और भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ. दिल्ली: यूनिवर्सिटी प्रेस.
5. कुमार, आर. (2022). वैश्वीकरण और भारतीय राज्य व्यवस्था. नई दिल्ली: सेज.
6. कुमार, एस. (2023). वैश्वीकरण और भारतीय नीतिगत परिवर्तन. वाराणसी: भारतीय प्रकाशन.
7. मिश्रा, ए. (2017). भारतीय राजनीति का वैश्वीकरण. लखनऊ: लोकभारती.
8. मिश्रा, आर. (2018). वैश्विक पूंजी और भारतीय लोकतंत्र. दिल्ली: ज्ञान पब्लिशिंग.
9. मिश्रा, वी. (2019). वैश्वीकरण और सांस्कृतिक राजनीति. नई दिल्ली: पियरसन.
10. नागर, ए. (2020). वैश्वीकरण और सामाजिक असमानता. जयपुर: रावत प्रकाशन.
11. नारायण, एस. (2021). स्वदेशी बनाम वैश्वीकरण: भारतीय राजनीति में विमर्श. नई दिल्ली: सेज.
12. पांडेय, ए. (2022). वैश्वीकरण और भारतीय राज्य की भूमिका. वाराणसी: विद्याभारती.
13. पांडेय, आर. (2023). वैश्वीकरण और चुनावी व्यवहार. इलाहाबाद: लोकभारती.
14. पाठक, वी. (2017). भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक वैश्वीकरण. दिल्ली: ऑक्सफोर्ड.
15. पटेल, ए. (2018). वैश्वीकरण और भारतीय समाज. अहमदाबाद: यूनिवर्सिटी प्रेस.
16. प्रसाद, आर. (2019). वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन. पटना: लोकभारती.
17. राव, एम. (2020). वैश्वीकरण और भारतीय संघीय राजनीति. हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान.
18. राव, पी. (2021). वैश्वीकरण और सार्वजनिक नीति. नई दिल्ली: सेज इंडिया.
19. सक्सेना, ए. (2022). वैश्वीकरण और भारतीय लोकतंत्र का विकास. दिल्ली: पियरसन.
20. शर्मा, ए. (2017). वैश्वीकरण और भारतीय आर्थिक विकास. नई दिल्ली: सेज.
21. शर्मा, आर. (2018). वैश्विक संस्कृति और भारतीय पहचान संकट. जयपुर: रावत.
22. शर्मा, वी. (2019). वैश्वीकरण और सामाजिक असमानता. दिल्ली: यूनिवर्सिटी प्रेस.
23. सिंह, ए. (2020). वैश्वीकरण और भारतीय राजनीति की दिशा. वाराणसी: भारतीय प्रकाशन.